GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO-93
ANSWERED ON-31/07/2024

PROGRESS OF EXPRESSWAYS IN WEST BENGAL

93. SHRI SAMIK BHATTACHARYA:

Will the Minister of ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS be pleased to state:

(a) the current status of the Kharagpur-Burdwan-Moregram Expressway, Gorakhpur-Siliguri Expressway, Varanasi-Kolkata Expressway and Raxual-Haldia Expressway passing through West Bengal;

(b) whether the land acquisition process has been completed for the West Bengal stretch of these expressways;

(c) the percentage of work completed for each of these four expressways in West Bengal; and

(d) whether there are any other expressways planned for development in West Bengal?

ANSWER

THE MINISTER OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(SHRI NITIN JAIRAM GADKARI)

(a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PARTS (a) TO (d) OF RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. 93 ANSWERED ON 31ST JULY, 2024 ASKED BY SHRI SAMIK BHATTACHARYA REGARDING **'PROGRESS OF EXPRESSWAYS IN WEST BENGAL'.**

(a) to (c) DPRs for Kharagpur – Burdwan - Moregram, Gorakhpur - Siliguri, Varanasi - Kolkata and Raxual - Haldia High Speed Corridors have been awarded. The award of civil work can be after the completion of DPR, statutory clearances and pre-construction activities depending upon projected traffic, techno - economic viability, availability of funds and inter-se-priority.

(d) Development of National Highways is a continuous process. Ministry keeps on receiving proposals from various State Governments including West Bengal for declaration/upgradation/development of NHs/Expressways. Decisions are taken based on the fulfilment of the criteria, requirement of connectivity, inter-se priority and availability of funds and synergy with PM Gati Shakti National Master Plan.

*****

भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं. *93

जिसका उत्तर 31.07.2024 को दिया जाना है

पश्चिमी बंगाल में एक्सप्रेसवे की प्रगति

*93. श्री सामिक भट्टाचार्य:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिमी बंगाल से होकर गुजरने वाले खड़गपुर - बर्दवान - मोरग्राम एक्सप्रेसवे, गोरखपुर - सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, वाराणसी - कोलकाता एक्सप्रेसवे और रक्सौल - हल्दिया एक्सप्रेसवे की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या इन एक्सप्रेसवे के पश्चिमी बंगाल खंड के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है;

(ग) पश्चिमी बंगाल में इन चारो एक्सप्रेसवे में से प्रत्येक एक्सप्रेसवे का कितने प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है; और

(घ) क्या पश्चिमी बंगाल में किसी अन्य एक्सप्रेसवे के विकास की योजनाएं हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

'पश्चिमी बंगाल में एक्सप्रेसवे की प्रगति' के संबंध में श्री सामिक भट्टाचार्य द्वारा पूछे गए दिनांक 31.07.2024 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. *93 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ग) खड़गपुर-बर्दवान-मोरग्राम, गोरखपुर-सिलीगुड़ी, वाराणसी-कोलकाता एक्सप्रेसवे और रक्सौल-हल्दिया हाई स्पीड कॉरिडोर के लिए डीपीआर सौंप दी गई है। डीपीआर पूरा होने, वैधानिक मंजूरियां मिलने और निर्माण-पूर्व कार्य-कलापों के पूरा होने के बाद अनुमानित यातायात, तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता, निधियों की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर सिविल कार्य सौंपा जा सकता है।

(घ) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास एक सतत प्रक्रिया है। मंत्रालय को पश्चिम बंगाल सहित विभिन्न राज्य सरकारों से राष्ट्रीय राजमार्गों/एक्सप्रेसवे की घोषणा/उन्नयन/विकास के लिए प्रस्ताव प्राप्त होते रहते हैं। इन पर निर्णय मानदंडों को पूरा करने, संपर्कता की आवश्यकता, पारस्परिक प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता तथा पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के साथ तालमेल के आधार पर लिए जाते हैं।

*****

SHRI SAMIK BHATTACHARYA: Sir, through you, I want to know this from the Minister. My question is regarding progress of four proposed expressways in West Bengal. Can the Ministry provide projected timelines for the completion of the Detailed Project Report (DPR), statutory clearances and pre-construction activities for the four expressways in West Bengal? And are there any land acquisition challenges related to their construction?

श्री हर्ष मल्होत्राः सभापति महोदय, इसका उत्तर दिया गया है। ये जो चारों राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, ये अभी डीपीआर स्टेज पर हैं। इसमें alignment आने और स्टेट गवर्नमेंट से कुछ clearances आने में समय लगता है। इसके साथ-साथ डीपीआर का भी काम चल रहा है। डीपीआर का काम समाप्त होने के बाद इसकी जो detailed projections है, वह आपको दे दी जाएगी।

SHRI SAMIK BHATTACHARYA: Sir, the Varanasi-Kolkata Expressway currently terminates at Uluberia in Howrah district. क्या सरकार की तरफ से ऐसा कोई प्रयास किया गया है कि इसको हावड़ा तक ही नहीं, बल्कि इसको कोलकाता तक ले जाया जाए? इसके साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि पश्चिमी बंगाल की तरफ से इसमें कितना सहयोग मिल रहा है? पश्चिमी बंगाल के ये जो चार एक्सप्रेसवे प्रपोज़्ड हैं, इनमें पश्चिमी बंगाल सरकार की क्या भूमिका है? खास करके वाराणसी से कोलकाता एक्सप्रेसवे में पश्चिमी बंगाल सरकार की क्या भूमिका है?लैंड एक्विजिशन को लेकर पश्चिमी बंगाल में बड़ी समस्या है। The West Bengal Government is not ready to acquire land. ...*(Interruptions)*... So, I want to know: What is the actual reality of this project?

श्री हर्ष मल्होत्रा : सभापति महोदय, जो वाराणसी-कोलकाता नेशनल हाईवे है, उसमें वाराणसी से झारखंड के बोकारो तक वर्क अवार्ड हो चुका है, क्योंकि वहां के राज्य की क्लीयरेंसेज़ समय पर आ गई थीं। उसे आगे कोलकाता तक जाना है, लेकिन उसमें एलाइनमेंट आने में देरी हुई है और अब एलाइनमेंट आ गया है। अभी यह डीपीआर स्टेज पर है और सरकार से इसकी नेसेसरी एप्रुवल्स आने के बाद इसका काम प्रारंभ हो पाएगा।

MR. CHAIRMAN: Supplementary no.3; Ms. Dola Sen.

सुश्री दोला सेन : चेयरमैन सर, हम पहले यह बोलना चाहेंगे कि पश्चिमी बंगाल में लैंड एक्विजिशन को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है।...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Please. ...*(Interruptions)*... Hon. Member is asking a supplementary. Please listen to her.

सुश्री दोला सेनः हमारी लीडर ममता बनर्जी जी ने लैंड एक्विजिशन को लेकर 26 डेज तक फास्टिंग मूवमेंट भी किया था।

MR. CHAIRMAN: Madam, please ask your supplementary.

सुश्री दोला सेन : इस पार्लियामेंट में दो बार ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, she is asking her supplementary.

सुश्री दोला सेन : इसी के कारण दो बार colonial Land Acquisition Act का अमेंडमेंट भी हुआ। We are grateful to her. Sir, through you, I want to ask the Minister: Is the Central Government following and obeying federal structure in coordination with the State Government, especially regarding land acquisition process over there? I also want to know whether the unorganised workers under these projects are getting minimum Central wage according to the law of the land.

श्री हर्ष मल्होत्रा : आदरणीय सभापति महोदय, लैंड एक्विजिशन नेशनल हाईवेज एक्ट के अंतर्गत प्रारंभ होता है। इसके लिए केंद्र की तरफ से "भूमि राशि" एक ऑनलाइन पोर्टल है, जिसके कारण लैंड एक्विजिशन ईज़ी होना शुरू हुआ है, जो पार्ट केंद्र को करना होता है। CALA अपॉइंटमेंट जरूर सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, पर वह राज्य के अधिकारी होते हैं और उसके बाद ही बाकी सारा प्रोसेस राज्य के अधिकारियों को, CALAs को करना होता है, इसलिए लैंड एक्विजिशन के majority of the part पर राज्य सरकार का दायित्व रहता है। हां, "भूमि राशि" पोर्टल शुरू करने के बाद, लैंड एक्विजिशन में जो पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को करना है, उसको हम एक्सपेडाइट कर पाते हैं। पहले लैंड एक्विजिशन में लगभग जो एक-डेढ़ साल लग जाया करता था, अब "भूमि राशि" पोर्टल के कारण उसमें बहुत कम समय लगता है। उसमें सेक्शन 3a से लेकर जो disbursement of amount है, वह हम " भूमि राशि" पोर्टल के कारण करते हैं। इसमें majority of the part स्टेट गवर्नमेंट को करना होता है। All workers are provided minimum wages as per the State labour laws.

MR. CHAIRMAN: Supplementary no.4; Shri Sanjay Kumar Jha.

श्री संजय कुमार झा : माननीय सभापति महोदय, इसमें एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेसवे है, जो गोरखपुर से सीतामढ़ी, मधुबनी, पटना, किशनगंज होते हुए सिलीगुड़ी तक जाती है। विभाग के द्वारा 31 मई को पत्र दिया गया, जिसमें बताया गया कि यह हाई स्पीड कॉरिडोर है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि इसका डीपीआर कब तक बनेगा, इसका निर्माण कब तक होगा? उस लेटर में यह भी बताया गया था कि इस काम को लेकर डिपार्टमेंट की तरफ से एक नोडल ऑफिसर भी बनाया जाएगा। कृपया माननीय मंत्री जी इस पर कुछ हाईलाइट करें।

श्री हर्ष मल्होत्रा : आदरणीय सभापति महोदय, मैं आदरणीय सदस्य महोदय को इसकी विस्तृत जानकारी दे दूंगा। वैसे, इसकी जो डीपीआर है, वह अभी प्रारंभ हुई है। डीपीआर पहला स्टेज होता है, फिर एलाइनमेंट और उसके बाद लैंड एक्वीजिशन होता है, तो इस स्टेज के आगे जाने पर जानकारी दी जाएगी।

MR. CHAIRMAN: Fifth supplementary, Shrimati Sulata Deo.

श्रीमती सुलता देव : धन्यवाद सर। सर, दिया हुआ प्रश्न पश्चिमी बंगाल के लिए है, मगर मैं आपके माध्यम से ओडिशा के बारे में पूछना चाहती हूं कि हमारे कटक-अनगुल नेशलन हाईवे -55 की बहुत दिन से डिमांड है। इसका काम क्यों कंप्लीट नहीं हो पा रहा है? यह एक death trap बन चुका है। हमारे ओडिशा के लगभग सभी सांसद प्रश्न उठा चुके हैं, कब तक यह National Highway-55 कंप्लीट होगा? इस death trap से लोगों को कब छुटकारा मिलेगा?

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister.

श्री हर्ष मल्होत्रा : सभापति महोदय, यह आज के प्रश्न के purview में नहीं है, इसके बारे में मैं माननीय सदस्य को विस्तृत जानकारी लेकर दूंगा।

MR. CHAIRMAN: Q.No.94, Dr. John Brittas.